P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-12* March- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत इजराइल सम्बन्ध : बदलते आयाम

दीपक कुमार सिंह
पूर्व शोध छात्र,
रक्षा अध्ययन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र भारत और इजराइल के बीच आए राजनीतिक संबंधों में बदलाव के दृष्टिगत भारत के लिए बने संभावित अवसर और रणनीतिक लाभ एवं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है। हाल ही में दोनों देशों के बीच रिस्तों ने नयी करवट ली है, जिसको लेकर दोनों तरफ से उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जिसका सीधा लाभ दोनों देशों को मिलेगा इन संबंधों से अरब देशों में भारत की भूमिका को भी नए तरीके से प्रभावित करता है। जहाँ अन्य देशों के साथ अच्छा संतुलन भारतीय विदेश नीति की दूरगामी आवश्यकता और सफलता को दर्शाता है वहीं फिलिस्तीन के बीच त्रिकोणीय संबंधों में आये रोचक बदलाव ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। अब यह नये बदलाव नये प्रतिमान और नई–नई प्रणालियों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और व्यापार की ओर अग्रसर है। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

मुख्य शब्द : Brownlie Ian, Basic Document in International Law, OUP, 1967 Hungligton Samuel P, Journal of democracy- Observer Research Foundation.

प्रस्तावना

भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंधों की औपचारिक शुरुआत 1992 (India & Israel Bilateral Relations, MoEA) में हुई किंतु इनके बीच संबंध इसके बहुत पहले से रहा है। 17 सितंबर 1950 में आजादी के तुरंत बाद जीविस एजेंसी ने अपना शरणार्थी शिविर खोला, जिसे बाद में व्यापारिक केंद्र के रुप में बदल दिया गया और अंततः 1992 में भारत और इजराइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधो की शुरुआत हुई। (India & Israel Bilateral Relations, MoEA) भारत से इनके सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध तो दो हजार सालों से भी अधिक पुराने है इसका कारण यह है कि दोनों ही विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहूदियों में भारत का सम्मान एक और वजह से भी रहा है कि यहूदी विश्व के कोने–कोने में पहुचे और उन्हें लगभग हर जगह जातीय हिंसा का दंश झेलना पड़ा किन्तु वे स्वयं मानते है कि भारत में उनके साथ दो हजार सालों के लम्बे सम्बन्ध होने के बावजूद ऐसा किसी प्रकार का भेद भाव या हिंसा नही हुई और यह उनके लिए विशेष भावनात्मक महत्व रखता है। इन सब के बावजूद भारत और इजराइल सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं थी। इसका कारण भारत इजराइल के संबधो का समुचित दोहन नहीं हुआ प्रायः इनके बीच के संबध दूसरे देशों के राजनयिक संबंधों में बाधा के तौर पर देखा जाता था जिसका सीधा असर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ा। किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा इस मिथक को तोड़ा गया और मध्य पूर्व व अरब देश और इजराइल के साथ अधिक संतुलित और सभी पक्षों के दृष्टि से लाभदायक सम्बन्ध बने हैं। भारत ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता 1950 में ही दे दिया था जबकि राजनयिक सम्बन्ध की औपचारिक शुरुआत 1992 में हुई जबकि इनके बीच राजनयिक संबंधों के पहले ही रक्षा सम्बन्ध थे। भारत और इजराइल दोनों एक दूसरे के अच्छे संबंधी देश थे। 1992 के पूर्व 1962, 65 और 71 की लड़ाई में इजराइल ने भारत को बिना शर्त समर्थन देने और रक्षा सामग्री की आपूर्ति करना इनके बीच के अच्छे संबंधों को दर्शाता है। यहां तक कि कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल द्वारा महत्वपूर्ण सामग्री बिना किसी भुगतान के उपलब्ध करवाना दोनों देशों के रिश्तों की गहराइयों को दर्शाता है। अब तक यह एक छुपा हुआ रिश्ता था जो पर्दे के पीछे काम करता था किन्तु विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसकी कोई औपचारिक मान्यता न थी। सबसे पहले जब राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई तो वह मुख्यतः रक्षा और कृषि संबंधी दो मुख्य स्तंभ थे किंतु बाद में इजराइल में अप्रत्याशित शोध एवं विकास की अद्भुत क्षमता ने भारत और इजराइल संबंधों को नया आधार दिया। इसका मुख्य कारण भारत संसाधनों से प्रचुर किंतु दोहन

क्षमता एवं तकनीकी इस्तेमाल में पिछड़ा हुआ राज्य है। इस प्रकार दोनों देशों के संबंध परस्पर सहयोगी एवं दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। भारत और इजराइल वर्तमान समय में एक दूसरे के पूरक राष्ट्र हैं। दोनों देशो की एक दूसरे की तरफ दिखाई देने वाली दिलचस्पी एक दुसरे की वर्तमान समस्याओं का समाधान भी दिखाती हैं और भविष्य के लिए संभावनायें भी हैं। एक ओर जहाँ भारत मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना के दम पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के ख्वाब से अपनी वर्तमान बेरोजगारी और आर्थिक असंतुलन को दूर करना चाहता है, वही दूसरी ओर इजराइल अपने सीमित संसाधनों की समस्या से आगे बढ़कर संभावनाओं भरे बाजार तक अपनी पहुच सुनिश्चित करना चाहता है।

भारत और इजराइल के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सहयोग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1992) के प्रारंभिक व्यापार से जिसमें मुख्यतः हीरा और अन्य बहुमूल्य पत्थरों का व्यापार था, वह व्यापार 2001 में 5.19 बिलियन डालर तक पहुंच गया हालांकि पिछले कुछ दिनों में फिर से दोनों में व्यापारिक संबंधों में गिरावट देखने को मिली किंतु नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने से इनके बीच के व्यापार में जो संभावनाएं थी वह पुनः वापस पटरी पर दौड़ी। इंडिया और इजराइल के बीच में व्यापारिक आदान–प्रदान चीन और हांगकांग के बाद तीसरे स्थान पर हैं। राजनयिक संबंधों में भी व्यापक सुधार हुआ है यदि निवेश की बात की जाए तो भारत इजराइल के बीच निवेश मुख्यतः शोध एवं विकास के क्षेत्र में है जो कि अब विविधता भरा क्षेत्र बनता जा रहा है।

भारत और इजराइल के बीच एक्शन प्लान 2012–15 बनाया गया जिसमें भारत–इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई जिसके 26 केंद्रों की स्थापना होनी है। रक्षा की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच रक्षा सम्बन्ध इनके बीच आपसी रक्षा उपकरणों का आदान प्रदान एवं इनकी सेनाओं द्वारा नियमित रूप से रणनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारत और इजराइल के बीच सामरिक कार्य दल का गठन अप्रैल 2017 में हुआ जिसमें भारत के युद्धपोतों और इजराइल के नौसेना सैनिक जहाजों के बीच मैत्री मुलाकात हाफिया पोर्ट पर हुई इसके अलावा रक्षा एवं सुरक्षा के अनेक क्षेत्रों जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हथियारों का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा आतंकवाद विरोधी कानूनों को मान्यता और क्रिमिनल मैटर इत्यादि पर अनेक समझौते हुए हैं। विज्ञानं और तकनिकी शोध पर इजराइल विश्व के अग्रणी देशो में से एक है। विज्ञान के क्षेत्र में भी 1993 से लेकर के अब तक विभिन्न समझौते हुए जिनके उद्देश्य और उपयोग का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब यह ज्ञान आधारित शिक्षा एवं तकनीकी का आदान प्रदान एवं समस्या आधारित अन्वेषणों पर पहुंच गया। भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक संबंध 2000 साल पुराने है। पर्यटन में 2017 के आकड़ों के अनुसार भारत से लगभग 45000 सैलानी इजराइल गए तथा लगभग 35000 इजराइल वासी भारत में पर्यटन के लिए आए।

शोध का उद्देश्य

भारत और इजराइल के बीच संबंधो में आये सकारात्मक परिवर्तन और मध्य पूर्व के साथ उन संबंधों के संतुलन को प्राप्त करने के लिए किये गये अभूतपूर्व प्रयासों और उसके वर्तमान और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करता है।

अध्यनकाल

2 वर्ष

साहित्यावलोकन

भारत इजराइल सम्बन्धों पर बहुत शोध कार्य हुए हैं किन्तु मेरा शोध पत्र समसामयिक है एवं 2014 में नई सरकार बनने के बाद आये नये आयामों को दर्शाता है।

बदलते आयाम

भारत और इजराइल इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों के २५ वर्ष मना रहे हैं और सही मायनें में यह दोनों के लिए सुखद स्थिति है जहाँ से असीम संभावनाओ का व्यापक द्वार खुल रहा है। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा कई तरीके से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। पहला यह कि यह यात्रा 6 दिन यानि सप्ताह भर चली जबकि आम तौर पर तीन–चार दिन में समाप्त हो जाती है। भारत द्वारा 6 दिन की राजकीय मेहमान नवाजी इन दो देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाता है। और दूसरा यह कि यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल यात्रा के मात्र 6 महीने के अंदर हुई। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा इजराइल के लिए की गई और मुखर होकर एक दूसरे को सहयोगी बताना दोनों देशों के रिश्तों का नया चेहरा सामने लाता है। इसके पहले इजराइल द्वारा महत्वपूर्ण मौकों पर सहयोग के बावजूद भारतीय विदेश नीति में यह पर्दे के पीछे चलने वाले संबंधो की तरह था जिस पर नई दिल्ली द्वारा स्पस्ट रूप से कुछ कहने से भी बचा जाता था। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को लेकर भारत एक दुविधा जनक स्तिथि मे रहता था। विश्व समुदाय में स्वतंत्रता और सम्प्रभुता का समर्थन करने वाला भारत और सबसे अधिक अपनी उर्जा जरूरतों को लेकर चिंता भारत और इजराइल सम्बन्ध में बड़ी बाधा माने जाते थे किन्तु यह अब बीते दिनों की बात हो गयी। वर्तमान यात्रा से पहले ऐसे नकारात्मक कयास लगाये जा रहे थे कि भारत और इजराइल के सम्बन्ध मध्य पूर्व और इस्लामिक देशों के साथ संबंधों में खटास लायेंगे और भारत के फिलिस्तिन से संबंधों और स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा किन्तु इन सब को झुठलाते हुए भारत ने इसराइल के राजधानी जेरुसलम स्थानातरित करने के प्रस्ताव पर नेगेटिव वोट करके यह स्पस्ट कर दिया कि दो देशो के सम्बन्ध एक दूसरे को ताक पर रखकर नहीं देखने होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत कि प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होंगे। इसका असर यह है कि भारत के जिम्मेदार राष्ट्रीय होने का सन्देश अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में और पुख्ता हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद यह भी अनुमान लगाये जाने लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू की प्रस्तावित यात्रा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा किन्तु प्रारम्भ में ही दिए गये अपने भाषण में उन्होंने यह भ्रांति दूर कर दिया कि एक नेगेटिव वोटिंग

हमारे बीच के मजबूत संबंधों में कोई मतलब नहीं रखता। इनके बीच संतुलन को इस बात से समझा जा सकता है कि रामल्लाह यात्रा पर गये मोदी से दोनों देशों ने उनके विवादों को लेकर भारत को मध्यस्तता करने का विचार सामने आया। जिसका अर्थ स्पष्ट है कि भारत विश्व समुदाय में अब अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने को तैयार है।

निष्कर्ष

इस प्रकार से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध ने भारत को विश्व पटल पर एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और वर्षों से मध्य पूर्व की जमी दुविधा को भी काफी हद तक कम करने का काम किया है जो क्षेत्रीय सम्बन्धों को नया आयाम देंगें तथा इस तरह भारत की विदेश नीति को यथार्थवादी आधार प्रदान करेंगें जो कि भारत के पक्ष में भी है और निश्चित रूप से यह भारत की स्थानीय और वैदेशिक दोनों जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होंगें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *Agrawal H.O. International Law and Human Rights, central law publication, 2009.*
2. *Brownlie Ian, Basic Document in International Law, OUP, 1967*
3. *Hungligton Samuel P, Journal of democracy.*
4. *Manish Kumar Jha, Benjamin visits India ISDA, on Indo Isarael agricultural partnership.*
5. *India & Israel Bilateral Relations unclassified bilateral brief, Embassy of India, created on 29 August 2017.*
6. *समाचार पत्रों के सम्पादकीय एवं ऑनलाइन संस्करणों जैसे & Dainik Jagaran, Economic Times, India Today, Indian EÛpress, Jansatta, The Hindu] The Hindustan Times, The Wire- (Accesed between 26 Feb 2018 to 1 march 2018)*
7. *Reports of ministry of foreign affairs.*
8. *Isda.com.*
9. *PIB newsletter.*
10. *Observer Research Foundation*